an>

Title: Shri K.C. Venugopal called the attention of the Minister of External Affairs on the situation arising out of Indians stranded in Iraq and steps taken by the Government in this regard.

HON. SPEAKER: Now, we shall take up Item No. 12 – Calling Attention.

Shri K.C. Venugopal.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and request that she may make a statement thereon:

"The situation arising out of Indians stranded in Iraq and steps taken by the Government in this regard."

**विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं "इराक में गृह युद्ध से उत्पन्न स्थिति" तथा "इराक में फंसे 41 श्रमिकों तथा उनके साथ वापस आने के इच्छुक शेष भारतीयों को भी वापस लाने की तत्काल आवश्यकता" के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इस सदन में उत्तर देना चाहूंगी।

प्रथमतः मैं इस सम्माननीय सदन में पुनः कहना चाहूंगी कि सरकार इराक में हाल ही के घटनाक्रमों तथा इराक में फंसे भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा एवं संरक्षा के संबंध में संसद के माननीय सदस्यों की चिंताओं से सहमत हूं।

भारत सरकार इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड शाम (आईएसआईएस) द्वारा अप्रत्याशित हमलों के परिणामस्वरूप इराक में जारी संघर्ष तथा बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को लेकर अत्यधिक चिंतित है। आईएसआईएस ने जिस गति से 8 जून को अपने हमले शुरू किए तथा उत्तरी एवं मध्य इराक के कई नगरों पर कब्जा किया, उससे हर कोई हतप्रभ है। तब से इराक में सुरक्षा की स्थिति गंभीर तथा अस्थिर बनी हुई है।

इस संघर्ष की शुरूआत में इराक में भारतीयों की संख्या लगभग 22000 थी। इनमें से बगदाद में 500, नजफ, में 2300, करबला में 1000, बसरा में 3000, कुर्दिस्तान में 15000 तथा अन्य शहरों में 200 भारतीय शामिल हैं। इन अप्रत्याशित हमलों के बाद संघर्ष के क्षेत्रों में कुछ भारतीय फंस गए थे।

तिकरित शहर के एक स्थानीय अस्पताल में कार्यरत 46 नर्सों का समूह भी संघर्ष के कारण फंस गया था। उन्हें एक अज्ञात समूह द्वारा 3 जुलाई को मोसुल लाया गया था। उन्हें 4 जुलाई को रिहा कर दिया गया था तथा उसी दिन उन्हें भारत वापस लाने के लिए एयर इंडिया के एक विशेष विमान की व्यवस्था की गई थी। वे विशेष विमान द्वारा 5 जुलाई की सुबह सुरक्षित कोच्चि पहुंच गई थीं, जिनके साथ 134 अन्य भारतीय कामगारों को भी वापस लाया गया था, जिसमें हैदराबाद में 80 तथा दिल्ली लाए गए 54 व्यक्ति शामिल हैं।

अध्यक्ष जी, मोसुल में एक विनिर्माण (कंस्ट्रक्शन) कंपनी में कार्यरत लगभग 41 भारतीय राष्ट्रिकों के अन्य समूह को एक अज्ञात गुट ने बंदी बना लिया था। सरकार उन्हें रिहा करवाने का भरसक प्रयास कर रही है तथा सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

भारत सरकार इराक में सुरक्षा स्थिति पर नियमित रूप से पैनी नजर रखे हुए है। इराक में इस संकट की शुरूआत से ही हमने 15 जून, 24 जून तथा 28 जून को हमारे राष्ट्रिकों को नियमित रूप से यात्रा परामर्शियां (ट्रैवल एडवाइज़रीज़) जारी की हैं। भारतीय राष्ट्रिकों को अगली अधिसूचना जारी होने तक इराक की किसी प्रकार की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा ईसीआर की श्रेणी के यात्रियों द्वारा उप्रवासन (इमिग्रेशन) पर प्रतिबंध लगा दिया है; जो 19 जून, 2014 से प्रभावी है।

हमने इराक में हमारे राष्ट्रिकों को पुनः सलाह दी है कि वे वाणिज्यिक माध्यमों (कमर्शियल मीन्स) से देश छोड़ दें, यदि ऐसा करना सुरक्षित है। वर्तमान सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले हमारे राष्ट्रिकों को यह सलाह दी गई है कि वे यथासंभव घरों के भीतर ही रहें तथा उत्पन्न सुरक्षा स्थिति से संबंधित उद्यतन सूचना तथा आवश्यक मार्गदर्शन के लिए बगदाद स्थित हमारे दूतावास से संपर्क में रहें। जिन भारतीय राष्ट्रिकों के पास यात्रा दस्तावेज़ नहीं हैं अथवा जिन्हें एयर टिकट जैसी अन्य कोंसुली सेवाओं तथा आप्रवासन अनापत्ति (इमिग्रेशन क्लियरेंस)के लिए सहायता की आवश्यकता है उन्हें सलाह दी गई है कि वे बगदाद स्थित हमारे दूतावास से सहायता प्राप्त करें।

अध्यक्ष जी, 15 जून से बग़दाद स्थित हमारे दूतावास तथा विदेश मंत्रालय ने विशेष नियंत्रण कक्षों में 24 घंटों की हेल्पलाइनें स्थापित की हैं ताकि इराक में हमारे राष्ट्रिकों तथा भारत में संबंधित परिवार के सदस्यों की सहायता की जा सके। इन हेल्पलाइनों के बारे में मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया है।

अध्यक्ष जी, हमने बसरा, नजफ तथा कर्बला में विशेष शिविर कार्यालय भी स्थापित किए हैं तथा अतिरिक्त 25 स्टॉफ सदस्य भेज कर बगदाद में अपने मिशन को सशक्त किया है। ये क्षेत्र कार्यालय भारतीय राष्ट्रिकों तथा जिन कंपनियों में वे काम करते हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं तथा उन्हें एयर टिकट प्रदान करके तथा साथ ही आप्रवासन व प्रस्थान सहायता करके हमारे राष्ट्रिकों को इराक छोड़ने की सुविधा प्रदान करने के लिए भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम लोगों ने अपने पूर्व राजदूत को इराक भेजा है जिससे हमारे राष्ट्रिकों की सहायता हेतु दूतावास द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सुदृढ़ बनाया जा सके और उनका समन्वयन किया जा सके। इराक में हमारे राष्ट्रिकों को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष का उपयोग किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रिकों की वापसी से संबंधित अंतर मंत्रालयी स्थायी समूह ने स्थिति की मांग के अनुसार इराक से हमारे राष्ट्रिकों को सुरक्षित तथा शीघ्र वापस लाने के लिए ठोस आपातकालीन योजनाएं तैयार की हैं। हालांकि हमने किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया है। फिर भी हम यात्रा दस्तावेजों तथा एयर टिकटों सहित हर अपेक्षित सहायता प्रदान कर के हमारे राष्ट्रिकों को वापस लाने के लिए या उन्हें इराक में अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाने की सुविधा प्रदान करने में लगे हुए हैं।

22 जुलाई की स्थिति के अनुसार 4000 भारतीय राष्ट्रिकों को भारत की वापस यात्रा के लिए सहायता प्रदान की गई है जिसमें शिविर कार्यालय की स्थापना के बाद से ही 3000 से अधिक राष्ट्रिकों के लिए एयर टिकटें शामिल हैं।

भारतीय राष्ट्रिकों, विशेÂष रूप से मौसुल में बंदी बनाए गए 41 भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा तथा संरक्षा हमारे लिए अत्यधिक चिंता तथा तत्काल कार्रवाई का मामला है। हम उनकी सुरक्षित वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह मैं आपको आश्वासन देती हूँ।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन को आश्वस्त करती हूँ कि हमारी सरकार का यह गंभीर प्रयास रहेगा कि इस समय इराक में प्रत्येक भारतीय नागरिक की सहायता की जाए और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए।

SHRI K.C. VENUGOPAL : I wish to express my sincere thanks to Madam. Speaker for giving me this opportunity for initiating such an important

subject like the situations in Iraq after the internal war of Iraq has broken

First of all, let me appreciate the Ministry of External Affairs and the Government of Kerala for their coordinating efforts to bring back 46 Malayali nurses from the captivity.

You know, Madam Minister, the Government of Kerala has done a lot of home work in this regard. Hon. Chief Minster of Kerala met you four times. The Government of Kerala has established their day-to-day contact, not only day-to-day contact but also minute-to-minute contact, with the Indian Embassy and the Malayali nurses, and the final result was that we are very much happy that all the 46 Malayali nurses were evacuated. But the report from Iraq was somewhat alarming after that, especially after 41 construction workers from Punjab were stranded in Iraq. Our External Affairs Ministry spokesperson confirmed the kidnapping of these 41 persons on 18th June. Already 45 days are over. What happened to them? If they are safe, what is the action taken by the Government for evacuating them? The entire country is watching this. The families of all these 41 construction workers are in deep concern, agony and pain. How can we tackle those families affected by this event? What is the step taken by the Government in this regard? Is there any diplomatic talk going on? There are some talks that they have asked for some ransom. Is it true or not? The country would like to know that.

Then, there is a feeling that the priority given to this issue has come down for some days because we are not hearing any response from the Government. We are not hearing anything as to what happened to these 41 construction labourers. If the Government of Punjab is aware of this fact, what is their role in this matter? The Government of Kerala has done a good role in bringing back those 46 Malayali nurses? I would like to know what role the Government of Punjab has done for bringing back these 41 construction workers.

Also, Subramanian Swamy Ji, the close aide of our Prime Minister, has already tweeted that Modi has ordered to send a battle ship with air cover to Iraq to rescue our people. Is that air cover already over? Is that air cover not functioning now? Anyway, you are taking advantage for the evacuation of the Malayali nurses. What exactly the Ministry of External Affairs and the Government of India have done in this regard? We would like to know this from you, Madam.

Also, there is an alarming report that around 6000 Indian people are stranded in various parts of Iraq after the civil war. What is the action taken by the Government of India? Is there any statistics with the Ministry of External Affairs? In today's reply of the hon. Minister, it is stated that as of 22nd July, over 4000 Indian nationals have been provided assistance for travelling back to India. This is what Madam has replied today. But yesterday I had a reply to a Starred Question from yourself only. That Starred Question revealed the total number of Indians who returned to the country from the civil war affected countries like Iraq, Afghanistan, etc. In respect of Iraq, your answer is, 2065 Indians have returned. This was the answer given on 21st July. The other was of 22nd of July. Why is this difference? Why is this conflict? It means that there is no specific record with the Ministry of External Affairs regarding the Iraq issue. This is what the general feeling. Therefore, we need an urgent and speedy action for evacuating the Indian nationals. We would like to know when these people, those who are stranded in Iraq due to the civil war, will be brought back. Therefore, I need a specific answer.

My second point is that I think the entire House will join me in appreciating the workaholic attitude of the Malayali nurses who are working all over the world. If there is a hospital in the world, there would be a Malayali nurse giving the message of Florence Nightingale. You know, these 46 Malayali nurses are all young girls with ages between 22 and 25. They went to Iraq for their livelihood. That is certainly all right. There are some issues of rehabilitation. I know Madam will answer that rehabilitation is not our duty but it is the duty of the State Government. I am also agreeing that this is not rehabilitation. The Government of Kerala is doing a lot of works. The Chief Minister called all the hospital owners and they are doing rehabilitation work in a commendable manner. But there are some issues for them.

These nurses have bought loan of Rs.2 lakh or Rs.3 lakh each from banks for their nursing studies. They are still repaying it. But, after this situation, how can they repay it? Therefore, I urge upon the Government to at least waive off loans of these Malayali nurses.

My second point is regarding their experience certificate. Those nurses, who have worked in Iraq, have not got their experience certificates. If they had got it, it would have been of benefit for them in their future endeavours. Therefore, your Embassy can help them in getting their experience certificates.

My third point is about their arrears. The nurses have also not got their arrears. In getting their arrears as well as experience certificates, the Embassy should intervene. Therefore, I seek the intervention of the hon. Minister of External Affairs in these three matters – waiving off loans, getting experience certificates and salaries.

Hon. Madam, I would not take much time of the House. But, the entire country is looking at the Government of India as to what they are going to do in case of 41 construction workers and the rest of the people, who have been stranded in Iraq. We need a speedy and effective action from the Government of India.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Madam Speaker. I express my sincere thanks to you in taking up this issue in Calling Attention Motion. I would also like to congratulate the Government of India, the Government of Kerala, especially Shrimati Sushma Swaraj ji, hon. Minister of External Affairs and hon. Chief Minister of Kerala, Shri Oommen Chandy. It has established a precedent in our country that if the State Government and the Central Government make a coordinated effort to meet the challenges, we will be able to succeed. It is a typical example; it is a model for which once again I take this opportunity to congratulate both Governments – the Central as well as the State – and our hon. Minister of External Affairs.

Madam, para 6 of the Statement is very alarming. It has already been enlightened by hon. Shri K. C. Venugopal by raising the issue of 41 citizens of our country, who are still in the captive state, and the steps to be taken in this regard. I do not know as to how the Government would explain it in the House, even though I would like to know as to what concrete action the Government would take to bring these people back to the country and

as to what diplomacy would be followed in this respect.

I would also like to know as to what measures the Government would take to rehabilitate those persons, who have already been brought back to the country. So, my main issue is about the rehabilitation of these people. It is because of the civil war in Iraq that they have been brought back. These people are nursing students and construction workers. So many NGOs and private entrepreneurs have come forward to help them.

I want to know as to whether the Government of India has formulated a package to rehabilitate these persons. So, some rehabilitation package has also to be announced as a part of the repatriation measure in respect of those who have come back to the country. So, I would like to seek these two clarifications from the Government.

**माननीय अध्यक्ष :** श्री धर्मवीर गांधी। केवल छोटा क्वैरिफिकेशन पूछना है, लंबा भाषण नहीं देना है।

**श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) :** मैडम, इस मुद्दे पर बोलने से पहले मैं इस बात का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमने इस मुद्दे पर जब भी विदेश मंत्री जी से मिलने की इच्छा प्रकट की, हमें टाइम मिला है, हर बार हम मिले हैं, हमें आश्वस्त किया है। सरकार ने जो काम का ब्यौरा दिया है, उसमें काफी अच्छा काम हुआ है परंतु कुछ मुद्दे हैं जिन पर अभी ध्यान देना बाकी है। खासकर मोसल में जो 41 पंजाबी बंधक फँसे पड़े हैं, ज्यों-ज्यों समय बीत रहा है, आशंकाएँ, अनिश्चितता, डर और भय का माहौल बना हुआ है, अफवाहें फैल रही हैं। पंजाब के लोग दिल्ली में आ चुके हैं। जंतर-मंतर पर हम लोग गए थे, हमारी पार्टी के हम चार एम.पी. गए थे, हमारी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल भी without any media glare, हम सब वहाँ उन लोगों के बीच बैठे। हमने मंत्री जी से भी बात की और मंत्री जी ने हमारे नेता भगवंत मान जी को आश्वासन दिया कि वे सभी ठीक-ठाक हैं। कल मैं दोबारा एक नई लिस्ट लेकर जो हमें पंजाब से मिली थी, मंत्री जी के पास गया। उन्होंने हमें फिर आश्वासन दिया कि वे ठीक-ठाक हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** कोई क्वैरिफिकेशन तो नहीं है आपका?

**श्री धर्म वीर गांधी :** महोदया, मेरी एक ही विनती है कि जब हम जंतर-मंतर पर पहुंचे तो हमने देखा कि केवल पंजाब से ही नहीं, बिहार से, यूपी से और राजस्थान से भी थे। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस मामले पर क्यों न एक नियत समय पर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलायी जाए, वैसे तो अभी तक बुलायी जानी चाहिए थी, ताकि लोगों को समय-समय पर इस मामले की जानकारी मिलती रहे और वह निश्चित और पुष्ट जानकारी अपने लोगों को दे सकें। हमारे कार्यकर्ता लगातार पंजाब में गांवों में जा रहे हैं और लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं, जो भी आश्वासन हमें सरकार देती है। परंतु अभी मैं समझता हूं कि बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि जो लोग बंधक बनाए हुए हैं, उनके अलावा भी हजारों लोग बंधकों जैसी स्थिति में हैं उनकी कम्पनी के मालिक हैं उन्होंने उनको बंधकों जैसी स्थिति में रखा है। उनको मोबाइल रिचार्ज नहीं करवाने दिया जाता है, इस कारण से वह घर पर सम्पर्क नहीं कर पाते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अगर सरकार के पास पुख्ता जानकारी है कि हमारे 41 नागरिक ठीक-ठाक हैं तो कृपया करके उनके परिवारों के साथ उनकी बातचीत करवा दी जाए ताकि उनको सांत्वना मिल सके, सहारा मिल सके और हौसला मिल सके। हमारी पार्टी के एक संसद सदस्य नार्वे में राजदूत रहे हैं, अगर उनकी सेवाओं की जरूरत हो, हमारी पार्टी की सेवाओं की जरूरत हो तो हम वह देने के लिए तैयार हैं।

SHRI BANDARU DATTATREYA (SECUNDERABAD): Madam, I thank you for giving me an opportunity to speak on this subject. मैं पहली बार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कम से कम दस हजार लोग गए थे। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने सभी को स्पेशल फ्लाइट से लेकर आयी हैं और उनकी पूरी देखभाल की है। मेरा इतना निवेदन है कि उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है। तेलंगाना के लोग बहुत गरीब हैं। यह लोग दुबई से ईराक गए और उन्हें इलीगल इमीग्रेंट होने की वजह से काफी परेशानी हो रही है। जिन्हें इलीगल इमीग्रेंट्स बताया जा रहा था, उनको सरकार बातचीत के द्वारा देश में लेकर आयी है। इसलिए मेरी मांग है कि उनके रिहब्लीटेशन के बारे में सरकार विचार करे।

**माननीय अध्यक्ष :** दत्तात्रेय जी, मैंने आपको स्पेशल केस के तहत एक-आध बात रखने के लिए बुलाया है, ज्यादा के लिए नहीं। आपकी बात आ गयी है।

CAPT. AMARINDER SINGH (AMRITSAR): Madam, on the same issue, I want to seek a clarification.

**माननीय अध्यक्ष :** इस पर डिसक्शन नहीं होता है।

CAPT. AMARINDER SINGH : Madam, this is just an intervention.

I want to say that though our concern is for all the Indians who are caught up in this turmoil in Iraq, but naturally our concern is also for natives of our State. As my colleague has raised, 41 Punjabi families are involved in this. I understand that they are in the clutches of some hostile groups and we do not know whether they want any ransom or in what condition those people are. They are in touch with our people. Our people in Punjab are in touch with them. So, they are very much there. They are in custody. We would like to know from the hon. Minister of External Affairs what the situation is and whether any effort is being made to get them released. This is what I want to know.

**माननीय अध्यक्ष :** चंदूमाजरा जी, आप भी यदि इस बारे में कहना चाहते हैं तो आपको संबद्ध कर देंगे।

**श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) :** स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जहां तक बंधकों की रिहाई का मामला है, इनकी कोशिशों के लिए पूरा देश प्रशंसा कर रहा है। मगर उनके परिवार के लोग ज्यादातर गरीब हैं, उनकी रोटी-पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है। हमारी पंजाब सरकार ने उनके लिए कुछ करने की ऑफर की थी और हम लोगों को उनके घरों में भेजा भी था। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि पंजाब सरकार की यह ऑफर है कि जो भी खर्च है, वह करने को तैयार है और गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया उनके परिवारों को सम्भालने के लिए कुछ मदद करे तो अच्छी बात होगी।

**श्रीमती सुषमा स्वराज :** अध्यक्ष जी, तीन माननीय सदस्यों ने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। लेकिन तीन और साथियों को भी आपने बोलने का मौका दिया।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** यह एक स्पेशल केस है। हमेशा ऐसा नहीं होना है।

**श्रीमती सुषमा स्वराज :** तीनों साथियों ने, जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, उन सब ने सबसे पहले सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है जो अब तक काम किया है। उसके लिए मैं उन सभी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूं क्योंकि बहुत ही कम होता है कि विपक्षी दलों से ऐसा सुर निकले। लेकिन मैं अभिभूत हूं इस बात से कि केरल के मुख्य मंत्री ओमन चांडी जी दो दिनों तक यहां रहे, चार बार मुझ से मिले, इकट्ठे हम ने रणनीति बनायी। उसके बाद जब यह सफलता प्राप्त हुई तो केवल उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी ओर से धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि केरल असेम्बली से

एक प्रस्ताव भी पारित करवाया जिसमें उन्होंने केन्द्र सरकार की प्रशंसा की। ऐसा बहुत कम होता है। उन्होंने बहुत ही मैग्नैनिमिटी दिखाई है कि जो हुआ है, उसे कोई माने भी। इसलिए मैं आप सब के प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि आप सब का ओपेनिंग सेन्टेन्स सरकार के प्रति आभार व्यक्त करने का था।

अध्यक्ष जी, उसके बाद कुछ प्रश्न उठाये गए हैं जो प्रश्न बहुत वाज़िब हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं अभी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि जो 41 लोग पकड़े गए हैं, वे सब पंजाब के हैं। कैप्टन साहब, वे सब पंजाब के नहीं हैं। उन 41 लोगों में से 31 पंजाब के हैं, 4 हिमाचल प्रदेश के हैं, 4 बिहार के हैं और 2 पश्चिम बंगाल के हैं। इस तरह से ये 41 बनते हैं। जहां तक यह सवाल है कि उन 41 लोगों के बारे में हमें कोई खबर है या नहीं तो चूंकि वे कैप्टिव हैं, मैं पहले यहां बता दूं कि यहां बहुत बार स्ट्रैंडेड शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी कैप्टिव शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है।

अध्यक्ष जी, इस समय इराक में जो लोग हैं, उन्हें मैं तीन श्रेणियों में बांटती हूं। एक श्रेणी हैं सुरक्षित (सेफ)। दूसरे हैं बंधक (कैप्टिव) , और तीसरे हैं फंसे हुए (स्ट्रैंडेड) । सुरक्षित वे हैं जो कुर्दिस्तान में हैं जहां किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो 22,000 लोगों की संख्या मैंने दी है, उसमें से 15,000 लोग कुर्दिस्तान में हैं। वे सुरक्षित हैं। बंधक हैं 41 जो कैप्टिव हैं, जिनके साथ हमारा कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं है, संपर्क टूटा हुआ है। इसीलिए, उन्हें हम बंधक कह रहे हैं। बाकी लोग, जिन्हें आप स्ट्रैंडेड कह रहे हैं, वे सब-के-सब फंसे हुए नहीं हैं। उनमें से स्ट्रैंडेड हम उन्हें कहते हैं जो भारत आना चाहते हैं, लेकिन जब वे अपनी कंपनियों से जाने के लिए कहते हैं तो कंपनी का मालिक उनका पासपोर्ट रख लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें पासपोर्ट नहीं दूंगा तो इस कारण वे आ नहीं सकते। या कंपनी का मालिक पासपोर्ट दे देता है और उनके पास टिकट का पैसा नहीं होता तो वे आ नहीं सकते। वे जो दो कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है या जिनके पास आने का पैसा नहीं है, उन्हें हम फंसे हुए की श्रेणी में रख सकते हैं।

अध्यक्ष जी, जहां तक फंसे हुए की श्रेणी का ताल्लुक है, मैं पूरी जिम्मेदारी से यहां खड़े होकर कह सकती हूं कि इराक में रहने वाला एक भी भारतीय नागरिक जो भारत आना चाहता है, चाहे उसके पास पासपोर्ट न हो, हमारे लोग उन्हें इमरजेंसी सर्टिफिकेट और यात्रा दस्तावेज दे रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं है, उन्हें टिकट दे रहे हैं और दोनों चीज़ों की सहूलियत प्रदान कर के उन्हें यहां ला रहे हैं। उन्हें केवल यहां ला ही नहीं रहे हैं, बल्कि जिस राज्य के वे होते हैं, उस राज्य के हर रेसिडेंट कमिश्नर और मेरे अपने मंत्रालय के अधिकारी उन्हें यहां रिसीव करते हैं। उसके बाद उन भवनों में उन्हें ले जाते हैं। उन भवनों में, जहां-जहां उन्हें आगे जाना है, उन्हें एयर टिकट देते हैं। अगर उन्हें हैदराबाद जाना है तो हैदराबाद की एयर टिकट देते हैं, तिरुवेंदूम जाना है तो तिरुवेंदूम की एयर टिकट देते हैं, कोलकाता जाना है तो कोलकाता की एयर टिकट देते हैं और उन्हें उनके अपने प्रदेश तक पहुंचाने का काम करते हैं।

अध्यक्ष जी, मुझे हैरानी हुई जब भाई के. सी. वेणूगोपाल ने कहा कि पहले आप ने 2065 का आंकड़ा दिया और आज आप 4,000 कह रही हैं। चूंकि हर दिन लोग आ रहे हैं इसलिए हर दिन आंकड़ा बदल रहा है। नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। जो आपके पास 2,065 का आंकड़ा है, वह किस जुलाई का है? मैं आज दिनांक 24 जुलाई को 22 जुलाई के आंकड़े दे रही हूं। अगर आज 24 जुलाई के आंकड़े दूं तो उसमें भी 150 लोग बढ़ गए होंगे तो यह आंकड़े का अन्तर नहीं है। पर, मुझे दुःख हुआ जब आप ने कहा कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है।

अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहती हूं कि केवल रिकॉर्ड नहीं, स्टेटवाइज रिकॉर्ड है मेरे पास कि एक-एक राज्य से कितने लोग आए हैं। मैं सम्माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि यह जो मैंने 4,000 लोग कहा, इसमें हमने 3,113 को खुद टिकटें दी हैं। बाकी वे लोग हैं जिन्हें उनकी कंपनी ने टिकट दे दी या वे संपन्न थे और अपने आप आए। मैं 3,113 लोगों का रिकॉर्ड स्टेटवाइज दे सकती हूं और आप कह रहे हैं कि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं हैं। आंध्र प्रदेश के, जब मैं आंध्र प्रदेश कह रही हूं तो यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कम्बाइंड है क्योंकि उनके पास अभी तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग फिगर्स नहीं हैं। आंध्र प्रदेश - 803, बिहार - 218, दिल्ली - 43, गुजरात - 77, हिमाचल प्रदेश - 22, केरल - 294, मध्य प्रदेश - 4, महाराष्ट्र - 38, पंजाब - 662। कैप्टन साहब, पंजाब से 662। राजस्थान 272, तमिलनाडु 23, उत्तर प्रदेश 385, वेस्ट बंगाल 132, उड़ीसा 11, हरियाणा 61, उत्तराखंड एक, असम एक, कर्नाटक पांच, जे. एंड के. एक, चंडीगढ़ एक, गोवा दो। किसी प्रदेश से एक व्यक्ति भी आया है तो उसका रिकॉर्ड भी मेरे पास है। इसलिए यह मत कहिए, वेणुगोपाल जी, कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं रखती। 3113 लोगों को हम अपनी टिकट देकर लाए हैं और उस टिकट का एक-एक का रिकॉर्ड हमारे पास है। ...(व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) :** 41 का क्या हुआ?

**श्रीमती सुषमा स्वराज :** अब मैं 41 पर आ रही हूं। जहां तक 41 का सवाल है, मैंने यह कहा कि सीधे हमारा कोई राब्ता उनसे नहीं है। लेकिन बहुत सोर्सेस, एक नहीं, एक सोर्स पर शायद मैं उतना विश्वास नहीं करती, बहुत सोर्सेस से हमें यह खबर मिली है कि वे सेफ और एलाइव हैं और उनको खाना दिया जा रहा है। वे कुशल हैं। यह मैं अन्य सार्सेस के हवाले से यहां कह सकती हूं। रही बात उनके परिवार वालों से मिलने की, आपने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या कर रही है। मैं यहां कहना चाहती हूं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ केरल ने अपने नर्सिस की चिन्ता की है तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उससे ज्यादा अपने इन 41 लोगों की और अपने लोगों की चिन्ता की है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि स्वयं बादल साहब मुझ से तीन बार मिले। एक बार उनके परिवार वालों के साथ मिले, एक बार सुखबीर सिंह बादल अलग से उनके परिवार वालों के साथ मिले। शिरोमणि अकाली दल का पूरा का पूरा प्रतिनिधि मंडल उन परिवारों के साथ आता रहा है। धर्मवीर गांधी जी कल जो कह रहे थे, परसों यहां हरसिमरत कौर बादल और भगवंत मान स्वयं उन सब लोगों के साथ मुझे मिले हैं। जिसमें 27 परिवार के लोग आए थे और मैं डेढ़ घंटा उनके पास बैठी। मैंने उन्हें एक-एक चीज बताई कि वे किस तरह से सेफ हैं। यह भी मैंने उन्हें बताया कि वे किस तरह से सेफ हैं। वेणु गोपाल जी पूछ रहे हैं कि अब उन्हें निकालने का एवशन प्लान क्या है। अगर एक्शन प्लान का ही मैंने खुलासा कर दिया तो फिर सारी गोपनीयता ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि बंधकों को निकालने का सबसे पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल यह होता है - सीक्रेसी, गोपनीयता। जब मैंने और वांडी जी ने मिल कर नर्सेस निकालीं तो आपको एवशन प्लान पता था। अलग-अलग लोग मीडिया में पता नहीं क्या-क्या कहे जा रहे हैं। कल कोई एक व्यक्ति दूसरे सदन में कह रहे थे कि केरल के एक व्यापारी उनको लेकर आए। मुझे तो केरल के किसी व्यापारी का नाम नहीं पता, कि कौन निकाल कर लाया। अगर कोई केरल का व्यापारी इतना ज्यादा मजबूत है कि निकाल कर ला सकता है तो मैं इस सदन में खड़े होकर उससे प्रार्थना करती हूं कि मेरे ये 41 बच्चे भी निकाल लाओ। पता नहीं, कौन-कौन क्या-क्या कह रहा है।

अध्यक्ष महोदया, मैं यह कह सकती हूं कि गल्फ कंट्रीस के सारे विदेश मंत्रियों से मैंने फोन पर व्यक्तिगत तौर पर बात की है। गल्फ कंट्रीस के सारे एम्बेसेडर्स को बुला कर मैंने बात की है। जिस देश से भी सहायता मिल सकती है, उस देश से मैंने सम्पर्क साधा है। मेरे लिए ये पंजाबी, बिहारी, तमिल, तेलगु, मलायलम नहीं हैं, ये मेरे लिए हिन्दुस्तानी बालक हैं और मैं उसी तरह से देख रही हूं, जैसे एक मां अपने बच्चों के लिए देखती है। जब वे परिवार वाले आए तो भी मैंने उनको यही कहा कि वे हमारे बालक हैं, हमारे बच्चे हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपको बताना चाहती हूं कि प्रधान मंत्री जी मुझ से हर दिन अपडेट लेते हैं। हर दिन शाम को मैं जाकर उनको बताती हूं कि आज कितने लोग आ गए और इन 41 के केसेस में हम कहां तक आगे बढ़े। बल्कि मैं आज आपसे कहना चाहती हूं, मैं चाहती थी कि यह चर्चा अगर हो जाए तो कम से कम सदन एक अपील करे, जिन लोगों ने उनको बंधक बना रखा है कि इराक और भारत के बहुत ज्यादा अच्छे रिश्ते रहें। इसी सदन में एक प्रस्ताव पारित करके कहा था कि भारत इराक में सेना नहीं भेजेगा, जिस समय लड़ाई भी हुई भारत एक ऐसा देश था, जिसने सेना नहीं भेजी थी। हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। आज यह सदन उन लोगों से अपील करे, जिन्होंने उन्हें बंधक बना कर रखा है, कि रमज़ान का महीना चल रहा है, इस रमज़ान में वे भारत को तोहफा देने का काम करें, हमारे वे बच्चे छोड़ दें, जिनको उन्होंने पकड़ रखा है। वे निर्दोष है, बेगुनाह हैं, उनका कोई गुनाह नहीं है और वे एक ऐसे मुल्क से संबंधित हैं, जो मुल्क उनके साथ दोस्ती रखता है। इसलिए आज इस सदन से अगर ये सुर जाए तो मुझे लगता है सबसे बड़ा एवशन प्लान, जो वेणु गोपाल पूछना चाह रहे हैं, इस सदन में मैं यह कहना चाहूंगी, हमने दिन-रात एक किया हुआ है। 24x7 हम लोग ये काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आज की इस अपील का और भी असर अगर होगा तो ईद से पहले रमज़ान के अंत तक वे बच्चे वापस आ जाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

â€¦(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** ऐसा होता नहीं है।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** रिकॉर्ड में ऐसा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी तो प्रशंसा की, सरकार की भी की। और केरल गवर्नमेंट की भी उन्होंने प्रशंसा की...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** यह रिकार्ड में नहीं जाना चाहिए?

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** वह नहीं, लेकिन सुषमा स्वराज जी ने यह कहा कि वेणुगोपाल जी ने बोला है कि गवर्नमेंट के पास कोई रिकार्ड नहीं है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने यह पूछा...(व्यवधान)

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** खड़गे जी, उन्होंने केवल यही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि एक में आंकड़ा 2065 है और दूसरे में चार हजार है। कोई रिकार्ड नहीं है, उन्होंने यह कहा।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** प्लीज़, सब लोग नहीं बोलें।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** उन्होंने यही कहा...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** वे खुद बतायें न।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के पास कितने लोग हैं, क्या है, इसका कोई अंदाजा है, क्या इसके बारे में कोई आंकड़े हैं, यह उन्होंने कहा। आपके पास आंकड़े नहीं हैं, यह नहीं कहा, हैं या नहीं, इसकी बात उन्होंने की। दूसरी चीज़, पैकेज के बारे में, रिहैबिलिटेशन के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में और लोन वेवर के बारे में उन्होंने पूछा है, उसके बारे में आपने नहीं बताया, वह जरा देख लें।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** राकेश जी, आपकी मंत्री जी सक्षम हैं।

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** खड़गे जी, पहले तो मैं यह बता दूं कि उन्होंने बाकायदा दो अलग आंकड़े देकर के मुझे कफ्यूज किया कि आपने एक आंकड़ा 2065 का दिया, आज चार हजार कह रही हैं, आपके एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के पास कोई आंकड़े नहीं हैं, यह बात कही, इसलिए मैंने उसका जवाब दिया। ...(व्यवधान) हां, पर वह तारीख अलग है न। जहां तक आपने लोन वेवर और इसकी बात की है, इसीलिए जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** ऐसा नहीं होता है, अब इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा।

**श्रीमती सुषमा स्वराज:** उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भी इसीलिए वह चीज़ काट दी गई थी, क्योंकि, वह स्टेट गवर्नमेंट का डोमेन है। वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डोमेन नहीं है। हम उनको उनके प्रदेश तक जब पहुंचा रहे हैं तो आगे उनको कोई नौकरी देना, आगे उनका पुनर्वसन करना, वह राज्य सरकारों का काम है और इसीलिए मैडम, जो आपने प्रस्ताव स्वीकृत किया था, उसमें से वह लाइन काट दी थी और केवल दो चीजें रखी थीं कि इराक में उत्पन्न स्थिति और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए एफर्ट्स, तक मैंने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दिया।

[Placed in Library, See No. LT 322/16/14]